GOVERNMENT BILLS

#The Appropriation (No. 4) Bill, 2013 (Contd.)

#SHORT DURATION DISCUSSION

Abnormal rise in the prices of onion and other essential commodities - Contd.

श्रीमती विमला कश्यप सूद (हिमाचल प्रदेश) : उपसभाति महोदय, आपने मुझे महंगाई पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

सर, हमारे देश में प्याज का उपयोग सभी घरों में होता है। इस प्रकार, प्याज हमारी खाद्य प्रवृत्ति का अभिन्न अंग है। पूरे देश में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, चाट स्टालों और प्रत्येक छोटे-बड़े भोजनालयों में ही क्या, शादी-ब्याह या कोई भी मौका हो, प्याज का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो प्याज सारे देश में होता है, लेकिन महाराष्ट्र में प्याज की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसमें नासिक का प्याज बहुत अच्छा भी माना जाता है। गुजरात, कर्णाटक, राजस्थान भी प्याज उत्पादक राज्य हैं।

प्याज की कीमत जब 80 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई, तो कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि प्याज की कीमत कब नीचे आएगी। इसकी पैदावार करने वाले प्रमुख राज्यों में बारिश की कमी की वजह से प्याज की आपूर्ति कम हुई है। कभी अधिक वर्षा की वजह से तो कभी कम वर्षा की वजह से प्याज की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परंतु, उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि इसके लिए परमानेंट प्रबंध कब होंगे? कोल्ड स्टोरेज आदि की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? अब तक 1 करोड़ 50 लाख टन प्याज का भारत में उत्पादन होता रहा है, परंतु सही रख-रखाव न होने से 50 प्रतिशत प्याज प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाता है। केवल प्याज ही नहीं, सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भी सब्जी 50-60 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है। दालें, खाद्य तेल आदि सभी की कीमतें आसमान छू रही हैं। महिलाओं को घर चलाना कठिन हो रहा है। रसोई गैस के सिलेंडर पर पहले से ही राशनिंग की गई है। गैस की कीमतें पहले ही इतनी बढ़ा दी गई है कि गरीब क्या, अब तो मध्यवर्गीय परिवारों की भी इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। किसान को उपज की, उनकी मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलती, उपभोक्ता को चीजें महंगी मिलती हैं, इस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? इसका सीधा-सीधा संबंध कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार से है और दूसरा, रुपये का गिरता मूल्य इसका जिम्मेदार है।

बाहर से कच्चा तेल और जो भी खाने-पीने का सामान आयात होगा, उसकी कीमत तो डालर में ही अदा करनी होगी। भारत अपनी कुल जरूरतों का 75 फीसदी तेल आयात करता है, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगा होगा। ऐसी स्थिति में माल की ढुलाई महंगी होगी तथा खाने-पीने की चीजें भी महंगी होंगी। देश में खाद्य तेल और दालों का भी भारी मात्रा में आयात होता है। 2012-13 में खाद्य तेल के आयात में 15.5 फीसदी का और दाल के आयात में 26.2 फीसदी का इजाफा हुआ

Discussed Together

है। आज डालर 65 रुपए का हो गया है। रुपये के गिरते मूल्य के कारण कीमतें और बढ़ जाएंगी। जब भारतीय जनता पार्टी और सभी अन्य पक्षों ने रुपये की गिरावट रोकने की बात की, तो सरकार ने कहा कि रुपये की हालत से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परंतु हम इसे खतरे की घंटी समझते हैं।

अभी खाद्य सुरक्षा विधेयक पास करने का ढिंढोरा पीट रही कांग्रेस से मैं पूछना चाहती हूं कि 9 वर्षों तक वह क्या करती रही? ऐसे तो कोई भी पार्टी चुनाव आने पर मतदाताओं को लुभाने के लिए उनके बैंक खातों में पैसा जमा करवा देगी। ऐसी कीमतों पर पकड़ होनी चाहिए। वह इस कुव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार को खत्म करे, तभी मूल्य वृद्धि रूकेगी और महिलाओं को घर चलाना आसान होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Bharatkumar Raut - not there. Now, Shri Ram Vilas Paswan.

श्री रामविलास पासवान (बिहार) : उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जो पूरक विधेयक आया है, इसको पास करना है, लेकिन मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो प्राइस राइज के संबंध में है और दूसरा बेरोजगारी के संबंध में है। यह जो मूल्य वृद्धि का मामला है, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब तक आप इस पर किसी न किसी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे, तब तक इस देश में बेचैनी रहेगी। अभी हम लोग चार दिन बाढ़ प्रभावित एरियाज में घूम कर आए हैं। अनाज या अन्य खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ने से गांव के लोग बहुत परेशान हैं। खास करके पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में पता ही नहीं चल पाता है कि यह कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। लोगों में हल्ला है कि पार्लियामेंट का सेशन समाप्त होने के बाद पुन: इनके दाम बढ़ेंगे। सरकार कहती है कि यह प्राइवेट कंपनी का मामला है, उसमें हम क्या interfere कर सकते हैं। हम सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि विदेश में जो प्राइस है, विदेश में जिस दर पर पेट्रोल या डीजल मिल रहा है और कब-कब कितना दाम बढ़ रहा है, जिस तरह से आप सेंसेक्स दिखाते हैं, उसी तरह से इसको भी उसमें क्लब कर दीजिए, जिससे लोगों को यह पता चले कि विदेश में किस दर पर पेट्रोल या डीजल मिल रहा है और हमारे यहां किस दर पर पेट्रोल या डीजल मिल रहा है। अब सारा का सारा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। एक्साइज टैक्स के कारण इसका दाम बढ़ जाता है। राज्य सरकार भी उतना ही टैक्स लगाती है। इसलिए, कम से कम यह तो पता चले कि आप किस दर पर पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने टैक्सेज हैं और कितने राज्य सरकार के टैक्सेज हैं। यह बहुत जरूरी है।

सर, दूसरी समस्या बेरोजगारी की है। इसमें दो मत नहीं है कि जब से यानी 1991 से उदारीकरण की नीति आई है, देश में रोजगार का साधन बिलकुल खत्म हो गया है। पहले कुछ ही युवाओं को नौकरी मिलती थी, मैं यह नहीं कहता हूं कि पहले सभी लोगों को नौकरी मिल जाती थी, लेकिन लोगों को एक आशा लगी रहती थी कि हमको भी नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में गांव के लड़के नहीं जा पाते हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं है। हम यूपीए गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि

[श्री रामविलास पासवान]

इसने चार-पांच अच्छे काम किए हैं और जिनमें "मनरेगा" भी एक अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन "मनरेगा" के अंतर्गत उन लोगों को रोजगार मिलता है, जो अनस्किल्ड हैं, जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं। जो पढ़े-लिखे लड़के हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं ला सकती है, यह हम जानते हैं। हालांकि हम लोगों ने शुरू से मांग की है कि यूथ कमिशन बनाइए, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़िए। यदि आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम सबको काम तो दीजिए।

सर, 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज फुटपाथ पर हैं, जो अपने आप अपना रोजगार चलाते हैं। सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे लोन नहीं चुका पा रहे हैं, लेकिन यदि इसका कुछ प्रतिशत पैसा भी इन लोगों को दिया जाए, जो लोग अपना रोजगार स्वयं चलाते हैं, जैसे चाय की दुकान है, पान की दुकान है, टैक्सी वाला है, तांगे वाला है, खोंचे वाला है, आदि, आप इन लोगों को 15 लाख रुपए दे दें और उनको कह दें कि आपसे हम कोई ब्याज नहीं लेंगे। आप उनसे ब्याज मत लीजिए और उनको कहिए कि आप पैसा लीजिए और दस साल, पंद्रह साल में पैसा रिटर्न कर दीजिए। मैं समझता हूं कि यदि इसको आप बेस बनाना शुरू करेंगे, तो कम से कम जो बेरोजगार है, वह अपना रोजगार स्वयं चला सकता है। आज होता यह है कि वह महाजन से पैसा लेता है और यदि वह महाजन से एक हजार रुपए लेता है, तो तीन महीने में उसको सूद के रूप में एक हजार रुपए चुकाने पड़ते हैं। यदि सरकार स्वयं उसके लिए पंद्रह लाख रुपए तक कर्ज दे और उसको कहे कि आप काम कीजिए तथा बीस रुपए या पच्चीस रुपए प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए, इस तरह से दस साल में आपको कर्ज समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप फिर पैसा लीजिए। यदि ऐसा होगा, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी चीज होगी। सर, लास्ट में हम एजुकेशन के संबंध में कहना चाहते हैं। आज पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। आज इनकी संख्या 20 गुना बढ़ गई है। जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनकी हालत बदहाल होती जा रही है। यहां हम लोगों में से ऐसे अधिकांश लोग हैं, जो गांव के स्कूल से पढ़ कर यहां आए हैं, लेकिन आज उन स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बिहार में जो टीचर्स हैं, उनको प्रति माह छः हजार रुपए दिए जाते हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : उनके तीन हजार रुपए बढ़ गए हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान : अच्छा। अब उनके तीन हजार रुपए बढ़ गए हैं, तो नौ हजार रुपए हो गए। ये नौ हजार रुपए तो इसी देश में कहीं-कहीं पर मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी के रूप में मिलते हैं। हम राज्य सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, राज्य सरकार के पास पैसे कहां हैं? आपका टोटल रेवेन्यू 14 हजार करोड़ रुपये का है, जबकि वहां 26 हजार करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के ऊपर दिए जा रहे हैं। **(समय की घंटी)**

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : हम अब खत्म कर रहे हैं, सर। हम यह मांग करेंगे कि यह जो एजूकेशन का मामला है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी हम चार दिनों तक फ्लड एरियाज में घूमकर आए हैं। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उसके बारे में मेरे स्पेशल मेंशन को मंजूर किया और इसलिए मैं उस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इसी के साथ, हम सरकार का समर्थन करते हैं और इस बिल का भी समर्थन करते हैं।

श्री उपसभापति : श्री बलविंदर सिंह भुंडर, नहीं हैं। श्रीमती गुन्डु सुधारानी, नहीं हैं। श्री राम कृपाल यादव।

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : महोदय, आज देश अर्थव्यवस्था के संकट से गुजर रहा है। मैं समझता हूं कि आज हर तरफ हाहाकार है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हर जगह परेशानी ही परेशानी है।

सर, महंगाई के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जब यूपीए-II सरकार बनी थी, तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने सबसे पहले देश से यह वादा किया था कि हम महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश को जो आश्वासन दिया था कि महंगाई कम होगी, वह कम नही हुई। आज प्याज की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसका आम लोगों पर बहुत खराब असर पड़ रहा है। आज हालत यह है कि कमाई करने के बाद भी लोगों को दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत, जो कि लगातार बढ़ रही है, उसके कुप्रभाव पड़े हैं और वह महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं समझता हूं कि जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक आप चाहकर भी महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे।

महोदय, मैं आपको बताऊं कि आज रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा है, लगातार डॉलर की कीमत से हमारे रुपये की जो कीमत घट रही है, उसका भी हमारी अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है, उसका 40 प्रतिशत हम बाहर से तेल आयात करने पर खर्च कर रहे हैं और बाकी जो बचता है, उसे हम सोना, दलहन और तिलहन आदि की खरीद पर खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस पर नियंत्रण करने की आज कोई कोशिश नही की जा रही है। वित्त मंत्री जी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, मगर उसका कोई असर नहीं हो रहा है।

[श्री राम कृपाल यादव]

महोदय, लोगों के उत्थान के लिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आज इस बिल के माध्यम से पैसा मांगने आए हैं और लोग पैसे देंगे भी, मगर आज सवाल यह है कि उस पैसे का कितना सदुपयोग हो रहा है? मैं आपको बताऊं कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना के लिए आप बिहार में करोड़ों रुपये दे रहे हैं। वहां अभी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें छः हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ। यह सीएजी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। वह किस चीज में हो रहा है? आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपका मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा में मजदूरों के रोजगार के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग यह हो रहा है कि उनके जॉब कार्ड नकली बनाए जा रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। मनरेगा की जो गाइडलाइन है, उसका डायवर्जन करके बिहार में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और वहां कार खरीदी जा रही है। हालत यह है कि उस योजना से आम लोगों को जो फायदा मिलना चाहिए था, उस गड़बड़ी की वजह से वह नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि जब केंद्र सरकार इसके लिए पैसे देती हैं, तो उस पर आप नियंत्रण करने का भी काम कीजिए और इसकी जांच कराइए। इतनी बड़ी राशि की जब लूट हो रही है, मैं यह केवल बिहार में देख रहा हूं, शायद पूरे देश में हो रही होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि इस पर कोई नियंत्रण करे, कोई स्टेप उठाए और कोई ठोस उपाय करने का काम करे। महोदय, शिक्षा जो महत्वपूर्ण योजना है, मैं समझता हूं कि शिक्षा में आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मगर उसकी गुणवत्ता क्या है। बच्चों को पढ़ाने की जो व्यवस्था आपने की है उसकी कितनी गुणवत्ता है? बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, वह बिल्कुल ही खराब हो रही है। वहां का बच्चा पढ़कर मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा, इस तरह की व्यवस्था है वहां पर। अभी रामविलास पासवान जी बतला रहे थे कि वहां पर टीचरों को 9 हजार रुपए मिल रहे हैं। 9 हजार रुपए में आप कैसे टीचर रखना चाहते हैं? तो ऐसे वहां के हालात हैं। वहां हजारों ऐसे स्कूल हैं जिन पर छत नहीं है वहां पर बेंच और कुर्सी की भी व्यवस्था नहीं है। वहां गरीब के बच्चे और खेत-खलिहान के मजदूरों के भी बच्चे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल में जो किताबें वगैरह जाती हैं,उसका भी वितरण ठीक नहीं है। ऐसी जो सारी व्यवस्था है, सरकार को चाहिए कि वह उस पर नियंत्रण करे। बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश, जो गरीबी से गुजर रहा है, अभी हमारे साथी बतला रहे थे कि हमारा बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। हमारे वहां कोई उद्योग नहीं है, हम सिर्फ खेती पर निर्भर करते हैं और अगर हम खेती पर निर्भर हैं तो वहां समूची स्थिति खराब है, क्योंकि वहां जल प्रबंधन नहीं है। आज बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों आ गए हैं, जिससे तबाही है। वहां के रहने वाले लोग, दस करोड़ से अधिक की आबादी के लोग जो खेती पर निर्भर रहते हैं, आज उनके साथ परेशानी है, जो निश्चित तौर से...***(समय की घंटी)***...बस खत्म कर रहा हूं।

आप पांच मिनट तो दे ही रहे हैं, एक-दो मिनट मेरे निवेदन करने से दे दीजिए। सर, मैं कह रहा था कि खेत और खलिहान में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए उपयुक्त व्यवस्था कीजिए। बिजली की व्यवस्था कीजिए।...**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please conclude. Okay. That's all.

श्री राम कृपाल यादव : डीजल महंगा है, जिससे वहां के लोग बहुत परेशानी में हैं। ...*(समय की घंटी)*... सर बोलने तो दीजिए।

श्री उपसभापति : मैं भी परेशानी में हूं, आप बैठिए।

श्री राम कृपाल यादव : बस, सर, एक-दो मिनट में खत्म कर दूंगा। सर, मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार जैसा प्रदेश, जहां आप कह रहे हैं कि हम बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिहार की जनता की डिमांड है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई स्टेप उठाइए। बिहार के खेत और खलिहान में काम करने वाले जो लोग हैं, वे आज भुखमरी की स्थिति में हैं, वहां कोई उद्योग नहीं हैं...*(व्यवधान)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point. बैठिए।

श्री राम कृपाल यादव : कम से कम किसानों को तसल्ली देने का काम करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए। बिहार जो बाढ़ और सुखाड़ से तबाह हो गया है, उसको सुधारने का काम कीजिए।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Mr. Mohammed Adeeb, you please start.

श्री राम कृपाल यादव : मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के किसानों, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं। आपके उद्योग चौपट हो रहे हैं। बाहर का माल देश में आ रहा है, चाइना यहां डम्प कर रहा है। हम तो सिर्फ बाजार बन कर रह गए हैं। इसका कारण है कि...**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Okay.

श्री राम कृपाल यादव : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more will go on record. ...*(Interruptions)*..... Now, Mr. Mohammed Adeeb, you please start. ...*(Interruptions)*..... That is not going on record. ...*(Interruptions)*..... Mr. Ram Kripal, it is not going on record. Now, Mr. Mohammed Adeeb.

श्री मोहम्मद अदीब (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन साहब, जिस चीज की चर्चा गांव, खलिहान, खेतों, बाजारों, सब तरफ हो रही है, आज हमारे दिल में ख्याल आया कि हम भी इस पर बात

---

*Not recorded.

[श्री मोहम्मद अदीब]

कर लें। यह सबसे अहम मसला था। हमारे अग्रवाल साहब ने उस वक्त यह मुद्दा उठाया था, जब प्याज की कीमत 80 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई थी। मैं समझता हूं कि यह मैन मेड प्रॉब्लम है। किसान बड़ी मेहनत से दो रुपए, तीन रुपए किलो में अपना आलू और अपनी सब्जी को बेचता है। 24 घंटे के बाद वह मंडी में 80 रुपए किलो और 90 रुपए किलो में बिकती है। यहां कमी किस की है, यह एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। लोग मुनाफाखोरी करते हैं। किसान को उसका हक नहीं मिलता, जो लोग मिडिल मैन हैं, वे इसको लूटते हैं, यह बात सरकार को मालूम है। मैं जानता हूं कि लखनऊ में महाजन लोगों ने महाजनी का काम बंद कर के गांवों, देहातों में मजदूरों व काश्तकारों को पैसा देना शुरू किया है। वे पैसा देकर उनकी खड़ी फसल खरीद लेते हैं। फिर उसे अपने गोदामों में रख देते हैं और अपनी मर्जी से मंडी में लाते हैं।

सर, इस मुल्क में दो चीजें हैं – एसेंशियल कमोडिटीज व लक्जरी कमोडिटीज। सर, उर्दू में एसेंशियल कमोडिटीज को जरूरियातें जिंदगी कहते हैं और जरूरियातें जिंदगी में खाने-पीने से जुड़ी चीजें हैं। उन से जुड़े गैर-कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ सरकार को कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए। खाने-पीने की चीजों में कानून की खिलाफवर्जी करने वाले लोगों को सख्त-से-सख्त सजा देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इनकी गैरे-कानूनी हरकतों का पता नहीं है। जो आसाइश-ए-जिंदगी या लक्जरी की चीजें हैं, उन पर हम इतने ज्यादा मेहरबान हो गए हैं कि शराब से लेकर चॉकलेट तक इम्पोर्ट करने को मजबूर हैं और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को बिठाने पर तुले हुए हैं।

मैंने दुनिया देखी है और दुनिया में किसी भी कैपिटल के 50 किलोमीटर के अंदर इतना बड़ा इंडिस्ट्रयल डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे यहां चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, फर्रुखाबाद हो, गाजियाबाद हो, यहां सुई से लेकर कारें तक बनती थीं। अब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन वह हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में बदल गई है। आज वहां जमीन के सौदे होते हैं, जमीन की कीमतें बढ़ाई जाती हैं और उसमें नंबर दो के पैसे बनते हैं। वहां बड़ी संख्या में मकान बनाए जा रहे हैं। आज एक-एक फेमिली 10-10 मकान खरीद कर रखती है और ये ज्यादातर सरकारी मुलाजिम व ऑफिसर्स हैं। उनके खानदान के लोग उन्हें खरीदते हैं। क्या सरकार इस पर सख्ती नहीं कर सकती? सरकार को चाहिए कि जिन्होंने एक से ज्यादा घर खरीदे हैं, उन पर टैक्स बढ़ा दें। उसे चाहिए कि जो लैंड इंडस्ट्रियल परपज के लिए अलॉट हुई थी, वहां इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, लेकिन हो यह रहा है कि हमारे हाथ की इंडस्ट्रीज, हमारी छोटी इंडस्ट्रीज इस देश से खत्म हो गई हैं। हम इम्पोर्ट करने पर dependent हो गए हैं। सर, इम्पोर्ट उन मुल्कों के लिए सही है, जिन की आबादी 1-2 करोड़ होती है, लेकिन जहां 125 करोड़ लोग हों, वहां हमें उन्हें रोजगार भी देना पड़ता है, जोकि छोटी इंडस्ट्रीज से डवलप होता है। इस का इल्जाम हम सब के ऊपर भी आता है। हमारे नेताओं में भी एक फैशन पैदा हो गया है। हम लोग भी काली-पीली सेक्युरिटी के

लोग लेकर चलते हैं, जिस पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर नेता इस काबिल नहीं है कि अपनी वाम के पास जाए तो उसे सेक्युरिटी की जरूरत क्या है? उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इस बारे में measures ले। हम सब के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। यह देश एक बड़े खतरे में पड़ा हुआ है। इस देश पर यह मुसीबत आ गई है कि जो सब लोग इस का इल्जाम देते हैं, वही टोपी लगाकर टेलीविजन के सामने कहते हैं कि महंगाई मार गई। हकीकत यह है कि हम सब लोग इस के लिए जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज सही नहीं हैं, कहीं-न-कहीं इन पॉलिसीज के implementation में कमी है। गवर्नमेंट अगर होर्डिंग को रोकना चाहे, तो रोक सकती है, गवर्नमेंट अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहे, तो कर सकती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो फाजिल चीजों के इम्पोर्ट पर रोक लगा सकती हैं और eessential commodities के लिए परमिशन दे सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो डॉलर 65 से 100 पर पहुंच जाएगा। सन् 1980 में मुझे अमेरिका में कहा गया था कि India will be on the top of the world. आज मुझे यह लगता है कि हम कहां-से-कहां पहुंच गए हैं? इसमें हमारी पॉलिसीज के Implementation में गलती है। यहां फाइनेंस मिनिस्टर और खाद्य मंत्री मौजूद हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि आप implementation को सख्त कीजिए, होर्डिंग को रोकिए, नहीं तो यह सब रूकने वाला नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

جناب محمد ادیب (اترپردیش) : ڈپٹی چئیرمین صاحب، جس چیز کی چرچا گاؤں، کھلیان، کھیتوں، بازاروں، سب طرف ہورہی ہے، آج ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی اس پر بات کرلیں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ تھا، ہمارے اگروال صاحب نےاس وقت یہ مدّعا اٹھایا تھا، جب پیاز کی قیمت اسّی روپے کلو سے اوپر پہنچ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین میڈ پرابلمس ہیں۔ کسان بڑی محنت سے دو روپے، تین روپے کلو میں اپنا آلو اور اپنی سبزی کو بیچتا ہے۔ چوبیس گھنٹے بعد وہ منڈی میں اسّی روپے اور نوّے روپے میں بکتی ہے۔ یہاں کمی کس کی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کی کمی ہے۔ جو لوگ منافہ خوری کرتے ہیں، کسانوں کو اس کا حق نہیں ملتا، جو لوگ مِڈل مین ہیں، وہ اس کو لوٹتے ہیں۔ یہ بات سرکار کو معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں لکھنؤ میں مہاجن لوگوں نے مہاجنی کا کام بند کرکے گاؤں، دیہاتوں میں مزدوروں و کاشتکاروں کو پیسہ دینا شروع کیا ہے۔ وہ پیسہ دیکر ان کی کھڑی فصل خرید لیتے ہیں۔ پھر اسے اپنے گوداموں میں رکھہ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے منڈی میں لاتے ہیں۔

سر، اس ملک میں دو چیزیں ہیں۔ ایسینشیل کموڈیٹیز و لگژری کموڈیٹیز کو ضروریاتِ زندگی کہتے ہیں اور ضروریاتِ زندگی میں کھانے پینے سے جڑی چیزیں ہیں۔ ان سے جڑے غیر قانونی دھندا کرنے والوں کے خلاف سرکار کو کوئی مروّت نہیں کرنی چاہئے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہئے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکار کو ان کی غیر قانونی حرکتوں کا پتہ نہیں ہے۔ جو آسائش

†Translitration in Urdu Script.

زندگی یا لگژری کی چیزیں ہیں، ان پر ہم اتنے زیادہ مہربان ہوگئے ہیں کہ شراب سے لیکر چاکلیٹ تک امپورٹ کرنے کو مجبور ہیں اور ہماری اپنی انڈسٹری کو بٹھانے پر تُلے ہوئے ہیں۔

میں نے دنیا دیکھی ہے اور دنیا میں کسی بھی کیپٹل کے پچاس کلومیٹر کے اندر اتنا بڑا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں چاہے نوئیڈا ہو، گڑگاؤں ہو، فرخ آباد ہو، غازی آباد ہو، یہاں سوئی سے لیکر کاریں تک بنتی تھیں۔

اب نوئیڈا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے، لیکن وہ ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بدل گئی ہے۔ آج وہاں زمین کے سودے ہوتے ہیں، زمین کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور اس میں نمبر دو کے پیسے بنتے ہیں۔ وہاں بڑی تعداد میں مکان بنائے جا رہے ہیں۔ آج ایک ایک فیملی 10-10 مکان خرید کر رکھتی ہے اور یہ زیادہ تر سرکاری ملازمین و آفیسرز ہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ انہیں خریدتے ہیں۔ کیا سرکار اس پر سختی نہیں کر سکتی؟ سرکار کو چاہئے کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ گھر خریدے ہیں، ان پر ٹیکس بڑھا دیں۔ اسے چاہئے کہ جو لینڈ انڈسٹریل پرپز کے لئے الاٹ ہوئی تھی، وہاں انڈسٹریز کو بڑھاوا دیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ کی انڈسٹریز، ہماری چھوٹی انڈسٹریز اس دیش سے ختم ہو گئ ہے۔ ہم امپورٹ کرنے پر ڈپینڈینٹ ہو گئے ہیں۔ سر، امپورٹ ان ملکوں کے لئے صحیح ہے، جن کی آبادی ایک-دو کروڑ ہوتی ہے، لیکن جہاں 125 کروڑ لوگ ہوں، وہاں ہمیں انہیں روزگار بھی دینا پڑتا ہے، جو کہ چھوٹی انڈسٹریز سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس کا الزام ہم سب کے اوپر بھی آتا ہے۔ ہمارے نیتاؤں میں بھی ایک فیشن پیدا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی کالی-پیلی سیکورٹی کے لوگ لے کر چلتے ہیں، جس پر لاکھوں-کروڑوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں۔ اگر نیتا اس قابل نہیں ہے کہ اپنی عوام کے پاس جائے تو اسے سیکورٹی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں۔ گوورنمنٹ کو چاہئے کہ وہ اس بارے میں میزرس لے۔ ہم سب کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔

یہ دیش ایک بڑے خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اس دیش پر یہ مصیبت آگئی ہے کہ جو سب لوگ اس کا الزام دیتے ہیں، وہی ٹوپی لگاکر ٹیلی-ویژن کے سامنے کہتے ہیں کہ مہنگائی مار گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں۔ گوورنمنٹ کی پالیسیز صحیح نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں اس پالیسیز کے امپلی-مینٹیشن میں کمی ہے۔ گوورنمنٹ اگرہورڈنگ کو روکنا چاہے، تو روک سکتی ہے، گوورنمنٹ اگر اسمال انڈسٹریز کو پرموٹ کرنا چاہے، تو کر سکتی

کے essential commodities ہے، گوورنمنٹ اگر چاہے تو فاضل چیزوں کے امپورٹ پر روک لگا سکتی ہے اور

لئے پرمیشن دے سکتی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، تو ڈالر 65 سے 100 پر پہنچ جائے گا۔ سن 1980 میں مجھے

آج مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں .India will be on the top of the world امریکہ میں کہا گیا تھا کہ

پہنچ گئے ہیں؟ اس میں ہماری پالیسیز کے امپلی-مینٹیشن میں غلطی ہے۔ یہاں فائنینس منسٹر اور کھاد منتری موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ امپلی-میٹیشن کو سخت کیجئے، ہورڈنگ کو روکئے، نہیں تو یہ سب رکنے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔

میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سخت کیجئے، ہورڈنگ کو روکئے، نہیں تو یہ سب رکنے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔]

श्री मनसुख एल. मांडविया (गुजरात) : सर, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात का भावनगर डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट - इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की टेरेटरीज से हिंदुस्तान के प्याज के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है। माननीय उपसभापति जी, जब किसान अपने यहां प्याज का उत्पादन करते हैं और उन्हें प्याज का पूरा पैसा नहीं मिलता, तो किसान रोते हैं और जब प्याज का भाव बढ़ जाता है, तो गरीब लोग रोते हैं।

महीने का उनका जो बजट है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। महोदय, मैं गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा था, इसलिए मुझे मालूम है कि भारत सरकार की जो आयात-निकास की नीति है, वह कैसी है। सर, किसान के यहां जो कुछ पैदा होता है, वह कितना पैदा हुआ, उसका कोई असेसमेंट नहीं रहता है। हमारे यहां जब माल पैदा होता है और आवश्यकता से ज्यादा माल पैदा हो जाता है, उस वक्त निकास नहीं होता है, लेकिन जब कम माल का उत्पादन होता है, तो निकास होता है, ऐसी स्थिति में आयात-निकास स्थिति का बैलेंस न होने की वजह से देश में प्राइस राइज होता है। प्याज का अभी जो प्राइस राइज हुआ है, प्याज की जो कीमत बढ़ी है, उसका मूल कारण वही है। सर, कुल मिलाकर देश में अभी जो सरकार चल रही है, उसकी आयात-निकास नीति भी ऐसी हो रही है। हमारे यहां जब उत्पादन होता है, उसमें किसान को सबसे शेयर करना होता है। पिछले साल हिंदुस्तान में कॉटन का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था और जब ज्यादा उत्पादन हुआ था, तो उस वक्त सरकार को एक्सपोर्ट करना चाहिए था। सरकार ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन तत्काल ऐसी कौन सी घटना घटी, किसके हित में, किसके लिए डिसीजन लिया गया कि कपास, कॉटन के निकास पर प्रतिबंध लगा दिया गया? जब किसान के कपास के निकास पर, एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसकी कीमत इतनी घट गई कि किसानों को मुश्किलें होने लगीं। हमारे यहां जो उत्पादन होता है, हमारे गोदामों में जब गेहूं और अनाज का भंडार होता है, उस वक्त निकास नहीं होता है, लेकिन जब हमारे यहां सूखे जैसी स्थिति का निर्माण होता है, जब हमारे यहां उत्पादन नहीं होता है, वैसी स्थिति में इन गोदामों से निकास होता है, यह कैसी नीति है? हिंदुस्तान में ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हो रहा है? इसलिए प्राइस राइज का effect गरीब के ऊपर, किसान के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। आज से दस साल पहले अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता था, सामान्य किसान होता था और अगर उसको मकान बनाना होता था, तो वह बना सकता था। शायद उसको बैंक से थोड़ा सा कर्ज लेना होता था, लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि सामान्य व्यक्ति अपना घर भी नहीं बना सकता है। क्या फायदा है बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने से? इस हाउस में कोई बिल लाने से क्या फायदा? आप एक बिल लाए कि सौ दिन का रोजगार देंगे, लेकिन कैग की रिपोर्ट आई है कि सौ दिन नहीं, आप एक वर्ष में दस दिन भी रोजगार नहीं दे पाए हैं, तो बिल लाने से क्या होगा? हमारे देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आना चाहिए। उनके हाथ में जो रोजगार आएगा, उससे स्किल डेवलप होगा। वे पैसा तो कमा लेंगे, अपना घर तो बना लेंगे और पैसा कैसे कमाना है, उसका स्किल डेवलप कर लेंगे। मेरी गुजरात गवर्नमेंट ने वह करके दिखाया है। आज हिंदुस्तान में जो सौ लोगों को नौकरी मिलती है, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि उसमें से 72 युवाओं को गुजरात में रोजगार मिल रहा है। उसका कारण क्या है? कारण है कि वहां स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। तहसील पर आई.टी.आई. खोले गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं, उनमें स्किल डेवलप

[श्री मनसुख एल. मांडविया]

करके युवा रोजी कमाते हैं। सर, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार का बजट 1000 करोड़ रुपए का है, जबकि मेरी गुजरात गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है। जब ऐसा होगा, तभी आप युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। उनके स्किल्स बढ़ाने चाहिए, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे।

माननीय उपसभापति महोदय, यह डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट sustainable होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। गांवों की हालत कैसी है? हमारे हुनरमंदों की हालत कैसी है? आजादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, कैसी नीतियों को उन्होंने इंप्लिमेंट किया कि हमारे यहां गांवों में जो हुनर था, वह हुनर अब नहीं रहा। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी गई।...**(समय की घंटी)**...आपने यूरोप की तरफ देखा, लेकिन विश्व में जो हो रहा है, वह हमारे देश में करना आवश्यक नहीं है। हमारे देश का जो स्किल है, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसके आधार पर अगर विकास होता, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Janardhan Waghmare. Take only two to three minutes.

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, thank you for giving me two minutes. Sir, India aspires to be a great world economy. But the harsh reality is that our economy is in a bad shape. It is in a shambles. Prices are rising. The prices of diesel and petrol have gone beyond our imagination. Inflation is on the increase. Our rupee is devalued to a great extent. Common man does not have any purchasing power at all. So, we are facing hard times. Despite our efforts, the growth rate is declining and, that is why, people are not in a mood to invest. Investors are not coming. Our exports have declined. A country, which simply depends upon imports, cannot strengthen its economy.

Sir, the youth of this country constitutes 50 per cent of its population. But there is unemployment. Young people are wandering here and there in search of jobs, and their education cannot help them. Our education is also in a shambles. Nearly 40 per cent vacant seats are there in universities. We are talking about the standard of education. Our Universities are not Centres of Excellence. And when there is no standard of education, you cannot train the manpower in the country. One good thing is there. In agriculture, our country has attained self-sufficiency, and that is the reason why we have been able to pass the Food Security Bill. This is, in fact, a very heartening thing. But farmers are still in peril. Thousands of farmers have committed suicides. What is the reason for this? The reasons are poverty and indebtedness. So, these are the problems. We should leave no stone unturned to improve our economy.

Sir, there was a time, during 60s and 70s, when Food Ministers used to visit advanced countries with begging bowls. Today we are self-sufficient in foodgrains. That is a vey good sign. But there are other problems. Our agriculture sector is in difficulties today. Eighty-one per cent of our farmers are marginal farmers. Their holdings are not more than two-and-a-half acres of land, and in the coming generation, it will, perhaps, come to down to one acre or half-an-acre. That is why we have to give financial help to these marginal farmers. There is labour crisis in agriculture. If you visit villages, you will find that no labourers are available. Even if they are available, the small farmers cannot pay their daily wages. Why don't we implement the NREGA in the farms of farmers so that we can help them to some extent? We have to, of course, find various solutions, various ways out, to solve the problems of the economy? If the economy is strengthened, then, the country is strengthened. With these words, I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. K.V. Thomas, would you like to intervene? ..*(Interruptions)*..

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति महोदय, उस दिन मोशन हमने शुरू किया था इसलिए जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा।...**(व्यवधान)**...हम उसका जवाब देंगे, तब मंत्री जी इंटरवीन करेंगे। तरीका यही है, यह परंपरा कैसे टूट जाएगी?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a Short Duration Discussion.

श्री नरेश अग्रवाल : एप्रोप्रिएशन बिल भी है, दोनों हैं।

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, we were told in the morning that both the private Member's business, that is, the Short Duration Discussion and the Government business, that is, the Appropriation Bill would be taken up together. That is why two Ministers, the Minister of Finance and the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, are here. So, as we started, the private Member's business ahead of Appropriation, let him briefly say something to maintain the tradition. That is it. And, then the hon. Minister can reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, see, Najmaji took the decision from there. Can I object to Najmaji's decision? I cannot do that.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: In deference to the fraternity of the Deputy Chairpersons, it is important for you to accept that.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, I wish I had that authority.

श्री नरेश अग्रवाल : उपसभापति जी, हम जल्दी खत्म करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, why I said, Najmaji, is that it is a Short Duration Discussion. She is very much knows that in Short Duration Discussion the mover has no right to reply. But, however, since you want to say in 2-3 sentences, you can say that.

SHRI NARESH AGARWAL: Sir, it is long duration discussion, not Short Duration Discussion. We have discussed it for more than 3 hours.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Take only 2-3 minutes. It is not a reply. Don't take it as a reply.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद अदा करूंगा जिन्होंने इसमें भाग लिया और मुझे खुशी है कि सभी दल चाहे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, सभी ने महंगाई पर चिंता व्यक्त की। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आप आंकड़ों पर न जाकर अगर सत्यता पर रहेंगे, तो जो परेशानी हमारे सामने, देश के सामने हैं, जिस पर हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसका कुछ समाधान हो सकेगा। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल था। माननीय वित्त मंत्री जी मैं जानता हूं कि आपने जो दिया होगा, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा हिस्सा नहीं होगा। चलिए, अब चुनाव आ रहे हैं, हम ज्यादा मांगना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से करीब 44 हजार करोड़ रुपये मिलने थे, पांच महीने में कुल 7401 करोड़ रुपए मिलें हैं और 37369 करोड़ रुपये अभी उत्तर प्रदेश के बाकी हैं। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का यह रूपया जल्दी अवमुक्त हो जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास रूक न पाए और उत्तर प्रदेश अपने विकास की ओर आगे बढ़ता जाए।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई दूंगा कि रिजर्व बैंक में नए गवर्नर आए हैं और कहीं न कहीं रुपया थमा है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक की पिछली नीतियां अच्छी नहीं थीं। अगर रिजर्व बैंक की नीति सही रही होती, तो शायद रुपये की हालत ऐसी नहीं होती, क्योंकि जैस ही नए गवर्नर आए अर्थ-व्यवस्था सुधरी, रुपया मजबूत हुआ, रुपये का गिरना बंद हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अब जो रिफॉर्म होंगे, अब जो निर्णय होंगे, वे निर्णय जरूर देश के लिए अच्छे होंगे। अगर इसी बीच सीरिया पर युद्ध हो गया, तो देश के सामने यह समस्या खड़ी हो रही है कि देश को फास्फेट मिलना बंद हो जाएगा। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है अगर एनपीके और डीएपी की कमी इस देश में हो गई, अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रभावित हो गया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का जो सुधार है, वह कृषि पर आधारित है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था कहीं चरमरा गई? तो मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार को एक ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से जिद कर रहा है, जी-20 में भी अमेरिका और रूस के बीच में टकराव हो रहा है, लेकिन उस पर अमेरिका राजी नहीं हो रहा है। सीरिया सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। अगर सीरिया पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, तो हिंदुस्तान की इकोनामी पर और प्रभाव पड़ेगा, हिंदुस्तान की अर्थ-व्यवस्था पर और प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी मंत्री जी कुछ जवाब दे दें कि रबी की फसल

का जो चालू सीजन आएगा, उस सीजन में डीएपी की और एनपीके की कमी तो नहीं होगी, इस देश के किसानों के सामने कोई समस्या पैदा तो नहीं होगी? मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित होगा - इससे किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा होगा। अगर कहीं होर्डिंग शुरू हो गई, मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया और होर्डिंग शुरू हो गई, तो किसानों को परेशानी हो जाएगी। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि प्रधान मंत्री जी ने हिंदुस्तान की अर्थ-व्यवस्था को सही करने के लिए जापान के साथ एक समझौता किया है। मैं कल इकोनामिक टाइम्स में देख रहा था, इकोनामिक टाइम्स ने एक सर्वे कराया कि देश का कारपोरेट जगत क्या चाहता है? उनका चौंकाने वाला सर्वे आया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप उस सर्वे के आधार पर जरूर कोई न कोई निर्णय लीजिए क्योंकि वह बहुत चौंकाने वाला है।...**(समय की घंटी)**...इसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तो कह दिया कि उद्योगपति जिसके साथ होते हैं उसको जनता कभी नहीं चुन सकती।

देश की जनता ने कभी किसी उद्योगपति को अपना नेता नहीं माना है। देश में कभी भी पैसे वाला आदमी पॉपुलर नहीं हो सकता है। जिसके साथ उद्योगपति है, वह कभी देश में नेता नहीं बन सकता है और वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। यही जीवन का सत्य है और यही हिंदुस्तान का सत्य है, चाहे आप हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देख लें। हमारा अर्थजगत, जिसको हम पूंजीपति कहते हैं, अगर उनकी यह सोच है, तो कहीं न कहीं आपकी पॉलिसी में कमी है और कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, इसलिए उद्योग की ग्रोथ रूकी है, उत्पादन घटा है और हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट घटा है और हमारे पास डॉलर की कमी होती जा रही है। हमारे पास सिर्फ तीन महीने का रिजर्व डॉलर है। हम लोगों के सामने यह स्थिति है।...***(समय की घंटी)***...मैं चाहूंगा कि हमें इस स्थिति पर चिंता करनी चाहिए। मैं यहां केवल प्याज की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश में एक कमी है कि मांग और मौजूदा स्थिति दोनों का हमारे पास कोई अध्ययन नही है कि किस सीजन में कितनी मांग होगी?...***(समय की घंटी)***...मैं समझता हूं कि इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए, आप जवाब देंगे। पूरे देश की जनता इसको सुन रही है और जनता को लगेगा कि यह सरकार महंगाई से चिंतित है और इस सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो देश की जनता को राहत मिल सकेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister. And I would like to repeat that it is not his reply on the Short Duration Discussion. It is his intervention on the Appropriation Bill. This is just to put it on record.

SHRI NARESH AGRAWAL: No. It is on both.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. I have already said it that this is not the reply. Yes, Prof. Thomas.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K. V. THOMAS): Sir, the discussion on the

4.00 P.M.

abnormal rise in the prices of onion and other essential commodities was started by the hon. Member, Shri Naresh Agrawal, on the 27th of August. It continued today. We are also discussing the Appropriation Bill.

Sir, altogether, 24 Members have participated in this discussion. I appreciate the concern of all the hon. Members who have raised issues relating to price-rise, especially the rise in prices of onion and other essential commodities.

Keeping prices under control and ensuring adequate availability of essential commodities is the commitment of the Government. We have taken a large number of administrative and fiscal measures.

Before getting into the details, I wish to refer to an analysis of the Wholesale Price Index (WPI), which gives an indication of the inflation for the last three years. It may not be very rosy, but it does not give a grim picture. Sir, the overall rate of inflation for all the commodities declined to 5.79 per cent during the month of July, 2013, when compared to 7.52 per cent during the month of July, 2012, a year ago.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Wholesale or Consumer Price Index?

PROF. K. V. THOMAS: I am talking about the WPI. I have got the details. I have got the details on the fiscal side also. Now, I am talking about the WPI. Fluctuation has been a regular feature in the rate of inflation in respect of food articles, even though, on the whole, I admit that it has been slightly on the rise.

The rate of inflation of this group, which was 10.17 per cent in July, 2012, was on the decline till October. There was, after that, an upward movement till this year January. This was followed by dips till this April, and again, it has gone up. So, there has been a widely an up and down movement of WPI, but it is one thing which gives signal that we are coming to a stable situation.

Sir, onion is one of the issues which has caused tears in the eyes of the nation. Sir, when I assumed the independent charge of this Ministry, one issue was the onion price rise, which was going up like anything. So, actually, Sir, in the case of onion, there are some historical facts. Sir, there is Rabi season, from March to June, which gives 60 per cent production in the country. Then there is Kharif season, from October to December, and late Kharif from January to March, which gives the remaining 40 per cent production. So, usually, the lean period is July to September to October. It is the period

we find the prices are shooting up. So, after a lot of consultations because of our experience in 2011, the Agriculture Ministry and our Ministry have started some measures. Sir, it is true that we are exporting onions because we have got a bumper production, and we have more onions being produced than what we need. But, as I said, in the lean months, from July to September and October, naturally, when the availability is less, the prices shoot up. So, what we have done is, we have constituted an Inter-Ministrial Committee with Joint Secretary (Commerce) as Chairman and Members from Agriculture, Consumer Affairs and NAFED and that Committee reviews every month, and we decide the Minimum Export Price, MEP. Because it was consciously a decision taken by Chief Ministers, and hon. Modi was Chairman of one of the Committees. So, one decision is we should not abruptly stop export or abruptly start import. That was the decision we have taken. So, this Committee will monitor the export and production and minimum export will be monitored in such a fashion that during the lean period of July to September and October, a meeting will be held. This is what we have done this year also. So, this year also, we have raised the MEP; so export is being cut.

Sir, in another 15-20 days, the production will go better. Now, the signs have come from many States because the new crop from Karnataka, Andhra and other States is now coming to the market. But, seeing this situation, during the last two years, the Ministry of Agriculture, through the NAFED, is writing to every State that NAFED is prepared to procure onions during the bumper production in a State and keep in storages, and when the lean season starts, NAFED is prepared to supply this stored onion to the deficient regions. Sir, this year also, we have sent the letter. We have called on the Agriculture Ministers, through NAFED, and have sent a letter in advance to all the consuming States that the NAFED is ready. We wrote that letter on 21.6.2013. Sir, before that, we have sent communications also. Unfortunately, during the last two years, the consuming States are not that much interested. That is one of the reasons. But still we are pursuing them. Sir, along with that, we have a Vegetable Initiative in Urban Clusters. Sir, very often the price rise is seriously felt in our metro cities. So, in 2011-12, the Agriculture Ministry with the assistance of the Finance Ministry moved a scheme called VIUC, Vegetable Initiative for Urban Clusters — it was in 2011-12— with an outlay of Rs.300 crores. This comes under the RKVY for which the Government of India is giving 100 per cent grant to States. This scheme aims to cover one city in each State. It was in 2011-12. The States can decide one city with ten lakh population or, maybe, less than that. This is in operation. So far for 2012-13 the outlay is Rs.300

[Prof. K.V. Thomas]

crores and for 2013-14 another Rs.200 hundred crores have been given. So, Sir, this is now in operation. What we have done under the scheme is that baseline survey is completed by engaging resource institutions, through small farmers, agri-business consortiums in all the metros and capital cities identified under the scheme to study such supply scheme and the only State which has not yet started it, is Karnataka. It has to start it. During 2012-13, BLS were conducted in the States of Haryana, Kerala, Odisha and Rajasthan. About 1.55 lakh farmers have been mobilized. Then we have 8036 farmers' interest groups and 64 farmers' producer organisations and 35 FPOs, which are in the process of legislation. Market aggregators have been identified in 17 States. Vegetable cultivation has been taken in 51,435 hectares covering open pollinated and hybrid vegetables. Besides, vegetable cultivation also has been taken up under protected cover, greenhouse and shade net house in 573 hectare area. Sir, Rs.290.71 crores has been released to the States in 2011-12 and Rs.192.63 crores in 2012-13 and in the coming years, it will be increased slowly depending upon the requirement of the States. This is a positive step which we have taken. This is one of the suggestions by the Modi Committee itself. So, we are taking care of that and this process is on. Sir, we also have a Market Intervention Scheme which has been under the Ministry of Agriculture. Sir, this Market Intervention Scheme, MIS, is being implemented on the request of a large number of States for procurement of agricultural and horticultural commodities. This may be for West Bengal. Tamil Nadu is also there. In the MIS the sharing is 75:25. If there is a loss, then 75 is shared by the Central Government and 25 by the State Government. So, the Government has taken a large number of steps so that we are able to control the prices of vegetables especially onion. Sir, this year our onion production has come down by about nine lakh tonnes, not much more than that. Sir, the difference between last year and this year export is about 1.5 lakh tonnes April to August. That is all. So, we also know that during this lean period some traders are making use of this opportunity to make some money. To implement the Essential Commodities Act is the duty of the State Governments. We are, along with State Governments, monitoring the situation, especially during this lean period. I have got a list of all the 35 States and UTs. Some of them have taken very strong actions. For example, Andhra Pradesh has conducted 9,847 raids and 45 people have been arrested; Gujarat has conducted 21,868 raids and 67 people have been arrested; Maharashtra has conducted 1,515 raids and has arrested 2,234 people; Uttar Pradesh has conducted 25,524 raids and has arrested 273 people. So, the main responsibility of implementing the Essential Commodities Act lies with the State Governments. I am not claiming that the implementation of the Essential Commodities Act is quite perfect. But, every year,

we have a discussion with the State Governments, especially before the lean season, so that effective steps can be taken by the State Governments. Fortunately, India is one of the agricultural countries, which produce a large quantity of agricultural products. We are also one of the largest consumers. Our agricultural sector is slowly growing now. Our farmers want a reasonable MSP. ...*(Interruptions)*.....

श्री राम कृपाल यादव : सर, दूसरे बिल पर भी हम लोगों को चर्चा करनी है, फिर हम लोगों को जाना भी है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is concluding. ...*(Interruptions)*..... You wanted a reply to price rise also. ...*(Interruptions)*.....

PROF. K.V. THOMAS: Sir, my point is that the Government has taken all possible steps to control the rising prices. At the same time, our agricultural production is enhancing. And, we are one of the agricultural countries in the world where we have started exporting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you very much. Now, the hon. Finance Minister.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, there has been a wide-ranging discussion on both, the price rise and on the Supplementary Demands in the Appropriation Bill. As many Members pointed out, the demands are very modest demands. In fact, the cash outflow is a very small amount. Most of the allocations are out of Rs. 5,000 crores, which were set apart in the Budget itself and made available to the Planning Commission in the expectation that some schemes will be announced in the Budget Speech and the Government may be required to announce some schemes post-Budget also. So, in anticipation of that, we had set aside Rs. 5,000 crores. And, most of the allocations to various schemes have been out of those 5,000 crores of rupees. So, there is really nothing new in those allocations; for example, for the women's bank, we are appropriating Rs. 1,000 crores, for the Nirbhaya Fund, we are appropriating Rs. 1,000 crores, for the Skill Development Mission, we are appropriating Rs. 1,000 crores. We are giving Rs. 100 crores to the Aligarh Muslim University and the Banaras Hindu University. These were all in the Budget Speech. The additional cash allocation is very small. And, the hon. Members have seen it in the Appropriation Bill. I won't take much time in going into the details of the Supplementary Demands in the Appropriation Bill. My colleague, Prof. Thomas, has explained you the situation regarding prices, with special reference to onion prices. As I said on another occasion, we are going through a period of stress. And, one of the causes of the economic stress is inflation.

[Shri P. Chidambaram]

It is true that in the last 15 or 16 years, we have had periods of low inflation; we have had periods of low inflation and low growth; we have had periods of low inflation and high growth and we also have had periods of high inflation and high growth. One could go into a theoretical explanation of why there is inflation. There are a number of factors that give rise to inflation. I do not wish to take the time of the House in explaining these factors. Some are factors that are the result of conscious policies. For example, if you increase, through a number of measures, farm wages, which is a good thing to do, it will have an inflationary impact. If you increase farm pricese which I strongly believe is a good thing to do, it will have an impact on prices. You cannot have a high price for paddy and a low price for rice. You cannot have a high price for wheat and a low price for *aata*. So, in a country where the farm wages are low and farm prices are low, yet, about 60 per cent of the people of the country depend, in one way or another, on agriculture, I think it is a good economic policy to increase farm wages and to increase farm prices. We can debate that. But I think it is good economic policy to increase farm wages and farm prices. When we do that, we will have to bear with a little inflation as a consequence of that.

There is another set of factors which are beyond our control. For example, when oil prices increase, it is completely out of our control. We do not fix oil prices. We had a period of low inflation, but let us also recall that that period witnessed the lowest oil prices in any five or six years period in recent times. Crude oil never crossed 32 dollars a barrel. I envy those who were in office at that time, because they were lucky. Crude oil was 32 dollars a barrel. But there was a point about seven years ago when crude oil went to 147 dollars a barrel. Until about 15 days ago, crude oil was in the range of about 100 to 103 dollars a barrel. Yesterday, it went to 115 dollars a barrel. We don't fix prices of crude oil. Therefore, that is a matter beyond our control. Likewise, edible oil and pulses. If a country is deficient in edible oil and pulses with regard to its requirements, there is no option but to import them. In fact, our policies have resulted in a very substantial increase in the production of edible oil and pulses domestically. But, still, there is a gap. Prices, again, are fixed by the countries which have exportable surpluses of edible oil and pulses. So, sometimes, and I say this with respect, we import some commodities which have a huge impact on inflation, the prices of which are beyond our control; therefore, we have to bear a price for that.

Then, there is a third set of factors. The third set of factors is what we do, what policies we follow and that is decided, largely, by the context. For example, Mr. V.P. Singh Badnore quoted me as saying that we allowed the fiscal deficit to breach the

target. We allowed the Current Account Deficit to swell. We took certain decisions in 2009 and 2011. And, he asked me who are you blaming? I say, "I am blaming nobody." The words I chose were very simple words. I said, 'We allowed the fiscal deficit target to be breached. We allowed the current account deficit to swell. We took some decisions in 2009-11.' Where is the blame in those three sentences? Look at the record. 'We' includes 'all of us' in Government, and, in a sense, 'all of us' in Parliament. Now, why did we do that? We had to do it at that time because there was a global crisis triggered by the collapse of the financial system in the US, and stimulus packages were considered the correct way to ensure that the growth was anchored and that growth did not collapse. Many countries adopted stimulus packages. India also adopted the policy of stimulus packages. The stimulus packages did anchor our growth rate. It didn't collapse like in Europe. In Europe, growth collapsed, and even today, the most powerful economic engine of Europe, Germany, is struggling to show positive growth. Barring two or three countries in Europe, all other countries are in recession. We staved off a recession. A recession will hurt a developing country very badly. We adopted consciously stimulus packages and we anchored our growth, but that resulted in some consequences. The fiscal deficit went beyond what, I would think, was acceptable limit. The current account deficit swelled and this also caused inflation.

Now, as I said, it is not my purpose to enter into an elaborate discussion on what happened. Now we have to look at what can be done to contain inflation. Obviously, what we can do is, focus on the supply side. I have got the figures of inflation before me. My learned friend read it. The WPI inflation is under control. It is roughly between 5 and 6 per cent. The WPI inflation is under control. In fact, core inflation, WPI manufacturing, is well under control. It is between 2 and 3 per cent. It is the Consumer Price Index, the CPI, the consumer inflation, which is very high, and, in consumer inflation, it is the food articles which are contributing to overall inflation.

The first answer is to focus on the supply side. In fact, we have done very well in foodgrains. We have increased production of fruits and vegetables and many other commodities, yet our distribution system is quite antiquated. There are too many inter-State and intra-State barriers and we do not have an efficient logistic system that brings produce to the stores and to the market place. We have to focus on the supply side and we have to focus on the distribution system. The second thing that we have to do is, to the extent possible, without constraining overall growth, we have to constrain demand which is why wasteful expenditure has to be curbed. Now, you can call it austerity measures, you can call it cut in non-Plan expenditure, but wasteful expenditure

[Shri P. Chidambaram]

must be curbed because that contributes to aggregate demand. While we must continue to spend and continue to find money for productive investment, any investment that is not productive, any investment that does not have any outcomes, is wasteful expenditure. So, some wasteful expenditure has to be curbed and, especially, when you are facing a rather grim inflation situation, wasteful expenditure has to be curbed.

The third thing that we have to do is to ensure that all inessential imports are curbed. When you have the money and when you are on a roll, you can import anything and it does not really make a big difference to the economy, but when you are facing a stressful situation, you have to curb inessential exports. We took a very small step; we said, high-end television sets of a certain size cannot be imported under personal baggage, because the very same set is produced in India and if a million sets are imported, that means, we lose foreign exchange, we lose customs duty and we lose the opportunity to produce a million sets in India. But there are citizens in this country who will complain against that measure. One of my friends here quoted a citizen's SMS. I respect that citizen and I don't know who he is, but there are citizens in this country who will mock at the Food Security Bill; there are citizens in this country who would say that MNERGA is a total waste. We are a plural society and there is space for every voice and every view, but we have to take some hard decisions to curb inessential imports. Essential imports that would keep the engine of the economy growing must be allowed, but inessential imports must be curbed. For example, why do we import coal? We have abundance of coal; we have tied ourselves up in knots; some other institutions have also tied strings around our hands and feet and, as a result, we have to import coal. Why do we import coal? Why should we import so much of metal scrap? Why do we not export the iron ore fines? Over a 100 lakh tons are lying on pit-heads and we don't export the iron ore fines, bulk of which is of no use in India. Therefore, we have to take some hard decisions. We have to speak to authorities, institutions and find ways in which we can curb import of inessential items and increase our exports. Many of these measures are being taken. Many more measures will be announced in the next few days and weeks. Some measures to curb inessential imports will also be announced, and I hope that all these measures taken together will have a beneficial impact on inflation. I am very concerned about inflation. It has often been said, I am not the author of this statement, but inflation is a tax on all sections of the people. In fact, it is an unequal tax on the very poor. Therefore, it is important that we contain inflation, and we will take measures to contain inflation. I have outlined some of them. My colleague has outlined some of them. We will take more measures to see to it that inflation is moderated.

There was some question about fuel prices fuelling inflation. True, fuel prices do fuel inflation. If crude oil prices go beyond a sustainable level of subsidies, some price-rise has to be passed through petrol and diesel and that, indeed, adds to inflation. No one in the Government can be happy increasing petrol prices or diesel prices. If we can afford the subsidy, we should provide the subsidy. To the extent that we can afford the subsidy, we are providing a subsidy, but when it reaches a point where the subsidy burden become very high and it is wrecking the balance sheets of oil companies or they cannot import any more crude oil nor will they get any credit from the banks, they tell us, there is no option but to pass on the prices. No decision has been taken and no decision will be taken hastily, and certainly, no decision will be taken without weighing the pros and cons and the larger public interest. What does the Government gain by taking a hasty decision that will put extra burdens on the poor? And, we are not fools on this side. Some decision has to be taken, but these are painful decisions which have to be taken keeping in view the larger interest. But, no decision has been taken so far.

The suggestion was made as to why we don't cut taxes. It is a very good suggestion. We can cut taxes. But, who is 'we'? 'We' is both, the Central Government and the State Governments. I don't think you should point a finger at the Central Government. However, if you point a finger, there are other fingers pointing to yourself. Look at what is collected by way of taxes. In 2011-12, the Central Government collected Rs.95,349 crore as taxes on crude oil and petroleum products. All the State Governments, put together, collected Rs.1,05,384 crore. In 2012-13, the Central Government collected Rs.98,592 crore. All the State Governments, put together, collected Rs.1,18,292 crore. If taxes must be cut, the Central Government must cut taxes. Equally, the State Governments also must cut taxes. And, there is another point. Out of the Rs.98,592 crore, that the Central Government collects, one-sixth goes to the States. So, you will have to add one- sixth of that to the States' kitty, and if you do that, the Central Government's stake, out of taxes from petroleum products, is only about Rs.82,000 crore and the State Governments' stake is about Rs.1,35,000 crore. Therefore, all of us can sit down together. If all of us decide that all right, even if it means sacrifice of revenue, let's cut some taxes, I am willing to sit down. We can look at how much we can cut, given our Budget requirements. But, if the Central Government cuts taxes, equally the State Governments also must cut taxes.

Sir, there was some question about the rupee. Again, without going into any theoretical exercise, I would like to submit that rupee does not have a fixed exchange

[Shri P. Chidambaram]

rate in India. We moved away from the fixed exchange rate to a market-determined exchange rate. And, I think that has been beneficial for the country. In fact, since 1991, all successive Governments have accepted that a market-determined exchange rate is a correct policy and we cannot go back to the pre-1991 fixed exchange rate policy. Let's look at the situation since 1998. In 1998, the value of the rupee was Rs.40 a dollar. It went down to Rs.44 a dollar in 2004, but it came back to Rs.40 a dollar in 2008. In an eight-year period, it moved from Rs.40 to Rs.44 and came back to Rs.40. Then, it went down to Rs.50 a dollar in 2009, but came back to Rs.44 a dollar in 2010. In one year - August 2011 to August 2012 - it depreciated from about Rs.45 a dollar to Rs.55 a dollar, but nobody noticed it because the ten rupee depreciation took place over a period of twelve months. When I took over in August, it was Rs.55 a dollar, and it remained at Rs.55 a dollar, or lower, for ten months - from August to May. I was very pleased with myself that the rupee was remaining stable for nearly ten months. Then came a policy statement by the U.S. Fed on May 22 that caused havoc in all emerging markets. Now, what does the G-20 say? Please read the communique. The G-20 leaders have all admitted and said that when the developed countries withdraw the policy followed by them — They call it 'quantitative easing'. We call it 'stimulus'. America calls it 'unconventional monetary policy' — it must be carefully calibrated and properly communicated to the markets. What happened on May 22 was a complete bolt from the blue. Without any kind of regard for what will happeni to emerging markets and without proper communication, a decision was announced by the US FED, yes, acting in their own self-interest, which has created turmoil in the emerging markets. All large emerging markets are affected, and, these are only half-a-dozen countries, Brazil, South Africa, Turkey, India and Indonesia. These are the countries which are affected, and, countries with a Current Account Deficit are, indeed, affected but in this turmoil, even a country with a Current Account Surplus is affected, like Malaysia. We are fighting many unknown factors in the currency market. Yes, the currency has appreciated in the last three, four days. It has gone back from 68.75 to about 65.24, but I keep my fingers crossed. I look at the NDF market at 7o' clock in the morning. The NDF market is 20 times larger than the Indian currency market. It is an off-shore market. We have no control over it. But measures are being taken, measures will be taken to increase the inflows of dollars into the country, and, one of the measures that we have taken, which many Members applauded, was that our friendly country, Japan, has agreed to a $50 billion swap with India, and, I take this opportunity to thank Japan for it. Japan is a true friend. BRICS have also agreed to create a $100 billion facility, with China taking the lead with $41 bn. I thank China, and, I thank all other countries for setting up this fund.

We have to look after ourselves. No developed country is going to look after our interests. We have to look after ourselves. The emerging economies, the developed countries have to get together. In BRICS, which is multi-lateral, India-Japan, which is bilateral, and we are looking at some other arrangements of a similar nature, not the same nature, but of a similar nature that will give us a much greater degree of comfort on the foreign exchange side.

Sir, we have had good times, we are going through a lean time. We have had the highest growth in UPA-I at an average of 8.6 per cent over a period of five years. We have had a slightly lower growth in UPA-II but, without meaning to score a point, the average growth rate during four years of UPA-II is still higher than the average growth rate of the NDA regime, and, I am not scoring a political point.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Mr. Minister, you built upon our legacy of 8 per cent in 2003. ..*(Interruptions)*..

SHRI P. CHIDAMBARAM: I did not want to score a point but you are trying to score a point, and, I don't want to get into an argument. Yes, you had one year of growth that followed the lowest growth rate since the turn of the century. The two years which witnessed the lowest growth rate, 4.3 per cent in 2000-2001, and, 4.0 per cent in 2002-2003, still remain the two dark spots since 2000.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: That was due to international sanctions and nuclear explosion. Please say that also. ..*(Interruptions)*..

SHRI P. CHIDAMBARAM: You are right. I am going to say. ..*(Interruptions)*..

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not going for a debate. ..*(Interruptions)*..

SHRI P. CHIDAMBARAM: If you sit down, I will say it. You faced a certain international situation, sanctions. We also face a similar international situation, namely, tapering, high crude oil prices and the European economy in doldrums. Every Government has to face a situation as it finds. You don't get an ideal situation. We are not playing this match on an astroturf. An astroturf is common at all times. Wherever you play the match, on the astroturf, the ground is common. We are playing this on a real turf, real ground, real pitch. Sometimes, the pitch enables a fast bowler; sometimes, the pitch enables a spin bowler, and, sometimes, the pitch enables a batsman. We are playing on a real pitch.You faced a pitch, you went through a period of pain, and in the last year of your Government, you showed growth of 7.5 per cent.

[Shri P. Chidambaram]

In the five years, as I said, although oil prices rose from 32 dollars to 147 dollars, we delivered 8.6 per cent growth, the highest ever since India got Independence. Never before did India witness 8.6 per cent growth for five years. In the first two years of the UPA-II, we were cruising along when the European crisis hit us. We are trying to find a way to brave the European crisis, the crisis of tapering of quantitative easing, and I want your support. All of us have to understand that we are more globalised, than we are willing to admit it. Every country is globalised today. We are more globalised, and we are willing to admit it. Financialisation of world markets will affect every country. Small countries are affected in a small way. Large economies are affected in a large way. But I have no doubt in my mind that we will emerge out of this lean period; we will emerge stronger. We must keep faith. We must not spread gloom or pessimism. We will emerge stronger just as you emerged after two years of pain. We will emerge stronger. I request this hon. House to keep faith in this country, its policies and vote the Appropriation Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Short Duration Discussion is over. I am now putting the motion moved by the hon. Minister to vote.

The question is:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2013-14, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Title were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Supplementary List of Business. The Minister wants to say something.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, Dr. Girija Vyas is in consultation with certain Members over the Street Vendors Bill. In the meanwhile, I want item Nos.2 and 3 to be taken up. I would request to pass the Rajiv Gandhi National Aviation University Bill which is given at Item No.2 .

श्री नरेश अग्रवाल : सर, स्ट्रीट वेंडर्स स्टेट का सब्जेक्ट है।...**(व्यवधान)**...हम लोग इसमें सहमत नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what he said. नरेश जी, वही कहा।

श्री राजीव शुक्ल : आप सुनिए तो सही कि मैंने कहा क्या है?

श्री उपसभापति : नरेश जी, उन्होंने वही कहा।

श्री राजीव शुक्ल : गिरिजा जी अभी बात कर रही हैं, तब तक हम आइटम नंबर दो और तीन ले लेते हैं, जिसमें राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी वाला बिल है और मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो मलबा उठाते हैं, मैला ढोते हैं, वह वाला है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not two hours. It will take only half an hour. ...*(Interruptions)*.....

श्री राजीव शुक्ल : तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नंबर दो बिना डिस्कशन के कर लें तो...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवाल : हम सहमत हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, इस पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत से मेम्बर्स ने मुझसे आग्रह किया है कि नंबर तीन पर आप बहस करा लें, बहुत लोगों को प्लेन पकड़ना है, आज अंतिम दिन है और उसके बाद नंबर दो को आप बिना बहस के पास करा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपसभापति : तो ठीक है। See, as suggested by hon. Minister and agreed to by all of you, we will first take up the Rajiv Gandhi National Aviation University Bill and pass it without discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I said, take up item No.3 first, because we have to speak on it. We will pass Item No.2 without discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAJEEV SHUKLA: It will take only two minutes. ...*(Interruptions)*.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill at item No.2 will be passed without discussion. ...*(Interruptions)*.....

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, clause-by-clause discussion will take time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill at item No.2 will be passed without discussion. It will take only five minutes. ...*(Interruptions)*.....Not even five minutes. ...*(Interruptions)*..... It will take only two minutes. ...*(Interruptions)*..... Second one will take only minutes.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there are three Bills. Whether you pass this first or that second, that does not matter. Let us agree which are the two Bills that you are willing to pass without discussion. ...*(Interruptions)*.... Tell us frankly. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: On the first Bill, we have reservations. Second one we are willing to pass without discussion. On third one, we want some discussion.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Then let us pass the second one first and then the third one. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I said. First we will pass second one without discussion. On the third Bill, there will be a brief discussion. So, now, Shri K.C. Venugopal.

The Rajiv Gandhi National Aviation University Bill, 2013

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI K.C. VENUGOPAL): Sir, I beg to move:

That the Bill to establish and incorporate a national aviation University to facilitate and promote aviation studies and research to achieve excellence in areas of aviation management, policy, science and technology, aviation environment, training in governing fields of safety and security regulations on aviation and other related fields to produce quality human resources to cater to the needs of the aviation sector and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 48 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.